PRGI : APHIN/26/A3657

पेन पॉवर

हिंदी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 1 अंक - 11 बुदवार, जुलाई 15, 2026 विशाखापट्टनम संपादक: गंट्यादा अप्पाराव पृष्ठों. 4 मूल्य. 1रु

नीतियां बनाना आसान है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही सबसे महत्वपूर्ण है: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 14 जुलाई: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वर्ष 2019 से 2024 के बीच राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पांच वर्षों के दौरान राज्य में व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ।

मंगलवार को मंत्रियों, सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में सभी ने सामूहिक रूप से कार्य किया और कल्याण, विकास तथा सुशासन का वास्तविक अर्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने सरकारी मशीनरी की सराहना करते हुए कहा कि उसने सरकार की सोच और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। उन्होंने कहा कि अपेक्षित बदलावों को कुछ हद तक हासिल किया गया है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी और सुधार की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समय–समय पर अपनी उपलब्धियों और प्रदर्शन की समीक्षा करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हर तीन महीने में कलेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (ळैक्च्) का नियमित विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण आंध्र 2047 विजन को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है। सरकार ने प्रति व्यक्ति आय और जीएसडीपी वृद्धि के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब तक 19 राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड बैठकों और 57 मंत्रिमंडल बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। चंद्रबाबू ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान उद्योगपतियों का आंध्र प्रदेश पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन अब वह विश्वास फिर से बहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश एक बार फिर निवेशकों की पसंदीदा मंजिल बन गया है और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहे हैं, जिससे रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित राज्य होने के साथ–साथ आंध्र प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि रायलसीमा में बागवानी और खनिज संसाधनों तथा तटीय जिलों में जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। साथ ही दुर्लभ खनिज (त्ंतम म्ंतजी डपदमतंसे), सिलिका और चीमकुर्थी ग्रेनाइट जैसे बहुमूल्य संसाधनों में वैल्यू एडिशन के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। चंद्रबाबू ने कहा कि नवाचार (Innovation) के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमारे पास तकनीक, संसाधन और ज्ञान है। आवश्यकता ऐसे नेतृत्व की है जो इनका प्रभावी उपयोग कर सके।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतियां बनाना आसान है, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही शासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब सरकार मासिक आर्थिक रिपोर्टों के आधार पर आगे बढ़ेगी और प्रत्येक महीने सचिवों तथा विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित कर प्रगति की समीक्षा करेगी।

मछुआरों के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार जगन के पास नहीं है: मंत्री अच्चेन्नायुडु

(पेन पॉवर न्यूज): अमरावती, 14 जुलाई: आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री किंजरापु अच्चेन्नायुडु ने विशाखापट्टनम दौरे पर गए वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जगन को मछुआरों के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अच्चेन्नायुडु ने कहा कि वाईएसआरसीपी के पांच वर्षों के शासनकाल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेक मछुआरों की मौत हुई थी और कुल 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इतनी गैर–जिम्मेदार नहीं है कि उन मौतों के लिए सीधे जगन को दोषी ठहराए।

उन्होंने सवाल किया कि उन 270 मृतकों में से एक भी परिवार से जगन अब तक मिलने क्यों नहीं गए।

मंत्री अच्चेन्नायुडु ने कहा: "कुल्हाड़ी पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी आज विशाखापट्टनम गए हैं। आपके पूर्व मंत्री सीदिरी अप्पलराजू के बेटे ने कथित रूप से अपने वाहन से एक व्यक्ति को टक्कर मारी थी। मुझे लगा कि आप उस पीड़ित को सांत्वना देने जा रहे होंगे। कुल्हाड़ी पार्टी झूठ की नींव पर खड़ी हुई है।

प्राकृतिक आपदा के कारण विशाखापट्टनम में छह मछुआरे लापता हो गए। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की पहचान ऐसी परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देकर लोगों की जान बचाने वाले नेता के रूप में है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन तकनीकी कारणों से नाव के डूबने का सटीक स्थान पता नहीं चल सका।"

मंत्री ने बताया कि 4 जुलाई को सुबह 10:30 बजे नाव के लापता होने की सूचना मिली थी। दुर्घटनाओं को रोकने और राहत कार्यों में सहायता के लिए सभी नौकाओं में ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोंडर से सूचना मिलते ही अधिकारियों ने स्थान का पता लगाया और सुबह 11:30 बजे भारतीय तटरक्षक बल (ब्वेंज ळनंतक) तथा भारतीय नौसेना (छंअल) को सूचित कर बचाव अभियान शुरू किया। अच्चेन्नायुडु ने आरोप लगाया कि जगन किलोमीटर और नॉटिकल मील के बीच का अंतर समझे बिना बयान दे रहे हैं। उनके अनुसार यह घटना तट से लगभग 11 नॉटिकल मील दूर हुई थी। उन्होंने बताया कि मत्स्य मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास और स्थानीय विधायकों को तुरंत पीड़ित परिवारों तथा बंदरगाह क्षेत्र में भेजा गया था। मंत्री ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार ने अपने कार्यकाल में मारे गए 270 लोगों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया, जबकि सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए सरकार ने यह सहायता प्रदान की।

वाईएसआरसीपी नेता मुद्रगड़ा पद्मनाभा रेड्डी का निधन

(पेन पॉवर न्यूज): काकीनाडा: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (ल्ैत्ब्च्) के वरिष्ठ नेता मुद्रगड़ा पद्मनाभा रेड्डी (73) का मंगलवार शाम निधन हो गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उपचाराधीन मुद्रगड़ा ने शाम करीब 6 बजे अंतिम सांस ली।

किडनी संबंधी बीमारी के कारण उन्हें 16 जून को हैदराबाद के गच्चीबौली स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से उनका वहीं इलाज चल रहा था। मंगलवार शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया।

मुद्रगड़ा पद्मनाभा रेड्डी का पैतृक गांव किर्लामपुडी, पूर्वी गोदावरी जिला है। उनका जन्म 22 जनवरी 1953 को हुआ था। वे पहली बार 1978 में विधायक चुने गए थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने चार बार विधायक, दो बार मंत्री और एक बार सांसद के रूप में सेवाएं दीं। विशेष रूप से वे कापू आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे। मुद्रगड़ा पद्मनाभा रेड्डी के निधन पर वाईएसआरसीपी के कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

मछुआरों के आंसुओं पर राजनीति बंद करें: पल्ला श्रीनिवास राव

(पेन पॉवर न्यूज): विशाखापट्टनम, 14 जुलाई: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक पल्ला श्रीनिवास राव ने वाईएसआरसीपी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को मछुआरों की पीड़ा पर राजनीति न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार समुद्र में लापता हुए मछुआरों के परिवारों को 72 घंटे के भीतर घ10 लाख का मुआवजा दिया गया।

मंगलवार को विशाखापट्टनम में विधायक रामकृष्ण बाबू और जिला पार्टी अध्यक्ष पट्टाभिराम के साथ मीडिया से बात करते हुए पल्ला ने समुद्र में लापता हुए मछुआरों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जगन से पूछा कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान मृत मछुआरों के कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया था। पल्ला ने आरोप लगाया कि जगन सरकार ने मत्स्य विभाग के धन का दुरुपयोग किया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में मृत हुए लगभग 63 मछुआरों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया है।

उन्होंने कहा कि जगन का मानवता की बात करना विडंबनापूर्ण लगता है। पल्ला ने कहा कि प्रभावित परिवारों से मिलने गए जगन ने यह नहीं बताया कि वे स्वयं कितना मुआवजा देंगे।

पल्ला ने आरोप लगाया कि जगन ने नौका दुर्घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाया और कहा कि घटना की जानकारी होने के बावजूद एक वाईएसआरसीपी नेता ने सरकार को समय पर सूचित नहीं किया। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर मछुआरे स्वयं जगन को जवाब देंगे।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे और दुर्घटना से बचे चिन्ना को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

पल्ला ने जगन पर "शव राजनीति" करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी के एक पूर्व मंत्री के बेटे की तेज रफ्तार बाइक चलाने से एक व्यक्ति की मौत हुई, और जगन उसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने जगन से ऐसी राजनीति छोड़ने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन प्रभावित परिवारों को घ1 करोड़ मुआवजा देने का झूठा वादा कर रहे हैं। पल्ला ने कहा कि मत्स्य मंत्री स्वास्थ्य कारणों से पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सके, जबकि जगन दुर्घटना के दस दिन बाद संवेदना जताने पहुंचे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान जालारिपेट मछुआरा गांव में टीडीआर अधिकार छीनने का प्रयास किया गया था।

"जगन के आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं": विधायक रामकृष्ण बाबू

टीडीपी विधायक रामकृष्ण बाबू ने कहा कि जगन मछुआरों के परिवारों से मिलकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए जगन ने मृत मछुआरों के परिवारों को घ5 लाख तक का मुआवजा नहीं दिया, जबकि अब घ1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि जगन सरकार के दौरान क्या 50 प्रतिशत सब्सिडी पर मछुआरों को एक भी जाल दिया गया था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हुदहुद चक्रवात के दौरान जगन विशाखापट्टनम के पीड़ितों से मिलने नहीं आए थे।

"वाईएसआरसीपी नेता की लापरवाही से मछुआरों की मौत हुई": टीडीपी जिला अध्यक्ष

विशाखापट्टनम जिला टीडीपी अध्यक्ष पट्टाभिराम ने कहा कि मछुआरे अब जगन पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि समुद्र में लापता हुए मछुआरों की मौत एक वाईएसआरसीपी नेता की लापरवाही के कारण हुई।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पालासा में वाईएसआरसीपी के एक पूर्व मंत्री के बेटे की लापरवाह बाइक ड्राइविंग से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। पट्टाभिराम ने कहा कि इस घटना से ध्यान हटाने के लिए ही जगन विशाखापट्टनम दौरे पर आए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मानवता की बात करने वाले वाईएसआरसीपी नेताओं की बातें अजीब लगती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मां और बहन के साथ न्याय नहीं कर सका, वह महिलाओं को न्याय कैसे दिला सकता है।

डोनेशन योजना में बदलाव, आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता :टीटीडी का महत्वपूर्ण निर्णय

(पेन पॉवर न्यूज): तिरुमला, 14 जुलाई: तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (ज्ज्क्) की बोर्ड बैठक मंगलवार को अध्यक्ष बी.आर. नायडू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 72 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

टीटीडी अध्यक्ष बी.आर. नायडू ने कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने नित्य हारती को लेकर नियमों की पूरी जानकारी के बिना टिप्पणी की है। उन्होंने बताया कि तिरुमला की परंपराओं और नियमों के बारे में उन्हें पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा।

बैठक में एटीसी के पास श्रद्धालुओं के लिए एसएसडी टोकन जारी करने हेतु स्थायी कतार व्यवस्था के निर्माण को घ6.31 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई। साथ ही कुमारधारा और पसुपु धारा क्षेत्रों में घ2.77 करोड़ की लागत से पुल निर्माण का निर्णय लिया गया।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जीएनसी क्षेत्र में 800 किलोवाट क्षमता की पवन चक्की (विंडमिल) स्थापित करने का भी फैसला किया गया।

अध्यक्ष ने बताया कि एसवी म्यूजियम में 12 वर्ष से अधिक आयु के आगंतुकों के लिए घ50 का प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। संग्रहालय के प्रबंधन को टाटा समूह को सौंपने का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा।

काकुला मानुकोंडा क्षेत्र में जमा हजारों टन कचरे को हटाने के लिए घ5 करोड़ मंजूर किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टीटीडी मंदिरों में घ2.35 करोड़ की लागत से अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

एटीसी और टीबीसी के पास स्थित 12 पुराने भवनों को हटाकर दानदाताओं के सहयोग से नए भवन बनाए जाएंगे। वर्ष 2027 की डायरी और कैलेंडर की छपाई के टेंडर न्यूनतम लागत पर मंजूर किए गए हैं।

ऑक्टोपस बेस कैंप में घ2.91 करोड़ की लागत से एफएमएस कार्यों के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

बैठक में ओंटिमिट्टा मंदिर के लिए स्वर्ण कवच तैयार करने हेतु एक किलोग्राम सोना उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई। घ17.86 करोड़ की लागत से 100 कमरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, ओंटिमिट्टा मंदिर की माडा वीधियों के विस्तार के लिए घ2.11 करोड़ मंजूर किए गए।

तातैया गुंटा गंगम्मा मंदिर के विकास के लिए घ2.5 करोड़ स्वीकृत किए गए। राज्य के प्रमुख मंदिरों में नित्य पारायण के लिए 791 वैदिक विद्वानों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। डीपीपी के कलाकारों के वेतन और भत्तों में वृद्धि का निर्णय लिया गया। साथ ही, 65 सर्वर पदों को कैटरिंग सुपरवाइजर पदों में पदोन्नत करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

डोनेशन योजना में बदलाव: ईओ रविचंद्र

टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी रविचंद्र ने बताया कि डोनेशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार की गई है। आम श्रद्धालुओं को दर्शन में अधिक प्राथमिकता देने के लिए दानदाताओं को मिलने वाली विशेष सुविधाओं (क्वदवत च्तपअप. समहमे) में कमी की गई है। रविचंद्र ने बताया कि नई डोनेशन नीति आज मध्यरात्रि से लागू हो जाएगी।

अमलापुरम में किसानों का प्रदर्शन, सिंचाई विभाग कार्यालय के पास तनाव

(पेन पॉवर न्यूज): अमलापुरम, 14 जुलाई: फसलों के लिए तत्काल पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को सिंचाई विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को धक्का देकर कार्यालय परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने सिंचाई विभाग के उप अभियंता (डीई) के कार्यालय के सामने धरना दिया, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। किसानों ने आरोप लगाया कि नहरों के आधुनिकीकरण के नाम पर पानी की आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी ठेकेदार का सहयोग कर किसानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। किसानों ने सिंचाई विभाग के डीई से मौके पर आकर जवाब देने की मांग की और विरोध स्वरूप उनके कार्यालय पर ताला लगाने की तैयारी की। हालांकि, पुलिस ने हस्तक्षेप कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसी दौरान सिंचाई विभाग के डीई श्रीराम जनार्दन वहां पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि गुरुवार शाम तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया।

संपादकीय

एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य पर दुनिया की नजर

पश्चिम एशिया में हालात धीरे–धीरे और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। होर्मुज जलडमरूमध्य में एक वाणिज्यिक जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। अमेरिकी फेडरल कमांड ने घोषणा की कि उन्होंने ईरान में कुल 14 ठिकानों पर हमला किया है। इससे नाराज तेहरान ने कई अरब देशों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। इन बढ़ते तनावों के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग के फिर से बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के मई माह के आंकड़ों के अनुसार, रूस से आयातित तेल की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। रूस से आयातित तेल पर प्रति टन 46 डॉलर का अतिरिक्त मूल्य चुकाना पड़ा। इसके कारण आयात का मूल्य 83 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि आयातित मात्रा में 2 प्रतिशत की कमी आई। यह सर्वविदित है कि यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बावजूद भारत ने सस्ती उपलब्धता के कारण रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप भारत में कच्चे तेल का भंडार प्रतिबंधों से पहले के स्तर तक पहुंच गया है। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में किसी एक देश से इतनी बड़ी मात्रा में तेल का यह सबसे बड़ा आयात है। यदि अभी होर्मुज जलडमरूमध्य बंद भी हो जाए, तो भारत को तत्काल कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि यह अवरोध कई महीनों तक जारी रहता है, तो गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत की आवश्यकता वाले हाइड्रोकार्बन, यानी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत एलएनजी और एलपीजी इसी मार्ग से परिवहन की जाती हैं। प्रतिबंधों में अस्थायी राहत के दौरान तेल रिफाइनरियों ने कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी का अग्रिम भंडारण कर लिया था, जिससे देश को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्काल लचीलापन मिला।

हालांकि, यदि होर्मुज मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो इस वर्ष मार्च और अप्रैल में देखे गए संकट की पुनरावृत्ति हो सकती है। भारत पहुंचने वाले कुछ गैस उत्पाद अंतरराष्ट्रीय समस्याओं या परिवहन में देरी के कारण प्रभावित हुए थे, लेकिन भारत ने अन्य स्रोतों के माध्यम से इस कमी को पूरा कर लिया। फिलहाल आवश्यक सामग्री उपलब्ध है। मार्च में आए संकट के बाद से भारत घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी और रसायनों की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए भारत साझेदार देशों के साथ बातचीत कर रहा है। दुनिया के कुल कच्चे तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत (पांचवां हिस्सा) और बड़ी मात्रा में एलएनजी होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, इराक, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित कई देश इसी मार्ग से कच्चा तेल भेजते हैं। ऐसे में यदि होर्मुज बंद हो जाता है, तो जहाजों को अधिक सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करनी पड़ेगी। इससे यात्रा समय और मालभाड़ा दोनों बढ़ेंगे, पेट्रोल और डीजल की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होगी तथा कीमतों में भारी उछाल आ सकता है।

भारत अपनी जरूरत का लगभग 89 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसलिए परिवहन लागत में वृद्धि का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका भले ही यह दावा कर रहा हो कि जहाज अभी भी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में सामान्य वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही लगभग बंद है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए कुछ तथाकथित "शैडो टैंकर ऑपरेशंस" के जरिए तेल का परिवहन किया जा रहा हो सकता है। इसे अवैध तेल तस्करी माना जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स के महानिदेशक अजय सहाय का मानना है कि फिलहाल जहाजों की आवाजाही को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों ने पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य से अपनी नियमित आवाजाही रोक दी है। वहीं, इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने वाली संस्था इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष पंकज चड्ढा का कहना है कि इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों के लिए जहाजरानी से ज्यादा चिंता गैस की उपलब्धता को लेकर है। उन्होंने बताया कि जब जलडमरूमध्य को खोलने संबंधी प्रारंभिक समझौता हुआ था, तब इंजीनियरिंग निर्माताओं को गुणवत्तापूर्ण गैस आपूर्ति मिलने लगी थी और 1 जुलाई से गैस की कीमतें भी किफायती हो गई थीं। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। उनका मानना है कि गैस की कीमतें फिर बढ़ सकती हैं और जो उद्योग अभी–अभी कमी के संकट से उबर रहे थे, उन्हें दोबारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

सतलुज की राजनीतिः एक ऐसी फिल्म जिस पर कोई भी दल पूरी तरह अपना दावा नहीं कर सकता

सतलुज फिल्म को लेकर उठे विवाद ने अब केवल एक फिल्मी बहस का रूप नहीं रखा है। यह पंजाब की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए एक राजनीतिक कसौटी बन गया है, जिसने 1980 और 1990 के दशक में उग्रवाद, आतंकवाद–रोधी अभियानों और मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर दशकों से चली आ रही राजनीतिक विरोधाभासों को उजागर कर दिया है।

कई वर्षों तक पंजाब की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों ने इस दर्दनाक दौर का सामना करने के बजाय उसे केवल एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में प्रबंधित करने की कोशिश की। लेकिन सतलुज ने इस संतुलन को तोड़ दिया है। अब हर बयान, हर चुप्पी और हर राजनीतिक रणनीति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।

सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं, बल्कि मानवाधिकार कार्यकर्ता ''जसवंत सिंह खालड़ा'' की पत्नी ''परमजीत कौर खालड़ा'' की ओर से आई है। जसवंत सिंह खालड़ा ने कथित रूप से अज्ञात लोगों के गुप्त अंतिम संस्कारों की जांच की थी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। हरिके पत्तन स्मृति समारोह से पहले जारी अपने कड़े संदेश में परमजीत कौर खालड़ा ने किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बख्शा। उन्होंने कांग्रेस पर व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों की निगरानी करने का आरोप लगाया, शिरोमणि अकाली दल की सरकारों पर ऐसे मामलों में आरोपित पुलिस अधिकारियों को संरक्षण और पुरस्कार देने का आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी सरकार पर दोषी अधिकारियों को न्याय के कटघरे तक लाने में विफल रहने का आरोप लगाया और विदेशों में कथित लक्षित हत्याओं को लेकर भाजपा–नीत केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए।

उनका यह हस्तक्षेप राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रत्येक दल की अलग–अलग कमजोरियां उजागर होती हैं। कांग्रेस के लिए ''सतलुज'' उस दौर की याद दिलाती है जब उसके शासनकाल में आतंकवाद–विरोधी अभियान चलाए गए थे और जिनसे जुड़े आरोप आज भी चर्चा में हैं। शिरोमणि अकाली दल के लिए, जो खुद को फिर से पंथक राजनीति के केंद्र में स्थापित करना चाहता है, यह फिल्म उसके शासनकाल पर भी सवाल खड़े करती है, जब आलोचकों के अनुसार गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

आम आदमी पार्टी, जो स्वयं को पारंपरिक राजनीति से अलग विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है, अब इस सवाल का सामना कर रही है कि क्या उसने वास्तव में इन लंबित मामलों को लेकर राज्य की नीति में कोई मूलभूत बदलाव किया है। दूसरी ओर, भाजपा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति और सिख समुदाय में राजनीतिक विस्तार के प्रयासों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है, जिससे यह मुद्दा उसके लिए विशेष रूप से संवेदनशील बन गया है।

परमजीत कौर खालड़ा का बयान किसी एक दल को नैतिक बढ़त देने के बजाय पूरे राजनीतिक तंत्र को कठघरे में खड़ा करता है। यही कारण है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर बेहद सावधानीपूर्ण रुख अपनाया है। उनकी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि वे अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के हिंदू और सिख मतदाता इस विषय पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।

भाजपा के लिए यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यदि वह राज्य के आतंकवाद–विरोधी अभियानों की आलोचना करने वाले किसी कथानक का समर्थन करती दिखाई देती है, तो उसके पारंपरिक समर्थक वर्ग का एक हिस्सा उससे दूर हो सकता है। वहीं, यदि वह सिख समुदाय की भावनाओं के प्रति असंवेदनशील दिखती है, तो पंजाब में उसके राजनीतिक विस्तार की संभावनाएं और सीमित हो सकती हैं।

कांग्रेस को ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार करने और अपने शासनकाल की राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने के बीच संतुलन बनाना है। अकाली दल अपने पारंपरिक पंथक समर्थकों को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन उसे अपने शासनकाल के रिकॉर्ड पर उठने वाले असहज सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार, जो बदलाव और स्वच्छ शासन के वादे के साथ सत्ता में आई थी, अब दबाव में है कि वह केवल यथास्थिति बनाए रखने के बजाय न्याय से जुड़े लंबित प्रश्नों पर ठोस कार्रवाई दिखाए।

हालांकि चुनावी परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि पंजाब में पंथक राजनीति समाप्त नहीं हुई है। 2024 लोकसभा चुनावों में खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा की जीत ने दिखाया कि सिख पहचान, न्याय और ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर राजनीति करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब भी पर्याप्त राजनीतिक स्थान मौजूद है।

अमृतपाल सिंह की जीत ने सिख पहचान और कथित अन्याय के प्रश्नों पर आधारित पंथक लामबंदी की निरंतर लोकप्रियता को दर्शाया। वहीं सरबजीत सिंह खालसा की जीत अपने आप में प्रतीकात्मक थी। वह बेअंत सिंह के पुत्र हैं, जो उन दो अंगरक्षकों में से एक थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी। उनकी जीत ने यह भी दिखाया कि 1984 और उसके बाद की घटनाओं की विरासत आज भी पंजाब के एक वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करती है। इन दोनों जीतों ने यह स्पष्ट किया कि पंथक राजनीति अभी भी चुनावी रूप से प्रासंगिक है, भले ही बार–बार यह दावा किया जाता रहा हो कि उसका प्रभाव कम हो गया है। ''सतलुज'' सीधे तौर पर इसी भावना को छूती है।

मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के लिए यही सबसे बड़ा द्वंद्व है। यदि वे चुप रहती हैं, तो पंथक राजनीति के लिए

राजनीतिक स्थान छोड़ सकती हैं। लेकिन यदि वे स्पष्ट रुख अपनाती हैं, तो विभिन्न समुदायों में वर्षों से तैयार किए गए अपने समर्थन आधार को जोखिम में डाल सकती हैं।

इसलिए, भले ही यह फिल्म तत्काल चुनावी परिणामों को न बदले, लेकिन इसमें राजनीतिक विमर्श और संदेशों को प्रभावित करने की क्षमता अवश्य है। यही कारण है कि ''सतलुज'' राजनीतिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण बन गई है।

यह फिल्म केवल पुराने घावों को नहीं कुरेद रही, बल्कि उन राजनीतिक सवालों को भी फिर से सामने ला रही है जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है कि पंजाब उग्रवाद और आतंकवाद–विरोधी अभियानों के दौर को किस तरह याद करता है, क्या विभिन्न सरकारों ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, और राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार तथा सिख पहचान जैसी परस्पर विरोधी धारणाओं के बीच राज्य किस प्रकार संतुलन स्थापित कर सकता है।

इन प्रश्नों पर शायद ही कभी राजनीतिक सहमति बन पाई है और यही पंजाब की राजनीति की सबसे स्थायी विभाजन रेखाओं में से एक हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो सतलुज अब केवल एक फिल्म नहीं रह गई है। यह राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुकी है, जो यह उजागर करती है कि राजनीतिक दल पंजाब के अतीत को किस तरह याद करते हैं और उसके भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

इंडो–पैसिफिक में चुपचाप हो रही है एक बड़ी क्रांति, और उसके केंद्र में है भारत

ऐसा प्रतीत होता है कि इंडो–पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत की परिकल्पना के आधारभूत ढांचे को तेजी से आकार दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दृष्टि को उन देशों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है जो वास्तव में इस क्षेत्र का हिस्सा हैं और जिनके इसके सफल होने में प्रत्यक्ष हित जुड़े हुए हैं। निस्संदेह अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह केवल प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया यात्राओं के दौरान घोषित अनेक पहलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी यात्रा से ठीक पहले हुई एक अन्य महत्वपूर्ण घटना ने भी इस व्यापक रणनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी देश लगभग समान क्षेत्रों में एक–दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनकी पहलें आपस में जुड़ी हुई एक जटिल रणनीतिक संरचना का रूप ले रही हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं।

परस्पर जुड़ी रणनीतिक कड़ियां

यदि इन यात्राओं को उनके अलग–अलग उद्देश्यों के संदर्भ में देखें, तो इंडोनेशिया आसियान का केंद्रीय देश है। वर्षों तक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मिलकर बने क्वाड ने आसियान की ''केंद्रीय भूमिका'' की बात तो की, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि इसे व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा। अब कम से कम भारत और क्वाड के दो अन्य सदस्यों के संदर्भ में यह लक्ष्य साकार होता दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने ऑस्ट्रेलिया–इंडोनेशिया कॉमन सिक्योरिटी संधि (जकार्ता संधि) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों को सुरक्षा खतरों पर परामर्श करने, रक्षा बलों की पारस्परिक कार्यक्षमता बढ़ाने और सैन्य शिक्षा आदान–प्रदान का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध करता है।

मार्च में जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए इंडोनेशिया गईं, जहां उन्होंने हथियारों और रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी देने वाले उन्नत समझौते पर हस्ताक्षर किए। शांतिवादी नीति के लिए प्रसिद्ध जापान के लिए यह एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसके साथ ही संवेदनशील सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए भी प्रोटोकॉल तय किए गए।

इसके बाद जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह सहयोग केवल ब्रह्मोस मिसाइल और एयर–टू–एयर मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं व्यापक है। इससे ठीक पहले, 2 जुलाई को जापान की प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ''पार्टनरशिप ऑफ स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस एंड ट्रस्ट'' समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन घटनाओं को एक साथ देखने पर ऐसा लगता है मानो रणनीतिक पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर बैठते जा रहे हों।

जमीनी स्तर पर सहयोग का तंत्र

यदि इन समझौतों को व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। ऑस्ट्रेलिया ने एक वरिष्ठ इंडोनेशियाई अधिकारी को अपनी रक्षा सेना में शामिल किया है और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारत ने इंडोनेशिया को भारतीय नौसेना द्वारा संचालित इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर दृ इंडियन ओशन रीजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और सूचना–साझाकरण केंद्र है, जो समुद्री डकैती, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों की निगरानी करता है। इसका अर्थ है कि दोनों देश वास्तविक समय में सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान करेंगे। जापान और इंडोनेशिया ने इंटीग्रेटेड डिफेंस डायलॉग मैकेनिज्म स्थापित करने और गोपनीय सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले से ही IFC&IOR का हिस्सा हैं और दोनों ने लॉजिस्टिक सहयोग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वे एक–दूसरे के बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग कर सकते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए सबांग बंदरगाह के संयुक्त विकास और अंडमान–आचेह संपर्क को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। अंडमान सागर में हाल ही में मिले विशाल गैस भंडारों के कारण सबांग बंदरगाह का महत्व और बढ़ गया है।

यदि नक्शे पर निकोबार स्थित नौसैनिक अड्डे, उन्नत हवाई पट्टी और ग्रेट निकोबार परियोजना को देखा जाए तो यह पूरा रणनीतिक ढांचा और स्पष्ट हो जाता है।

इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने ''कोको द्वीपों'' पर अपनी मौजूदगी मजबूत की है, जहां भारतीय नौसेना और वायुसेना नियमित रूप से तैनात रहती हैं। ऐसे समय में जब दुनिया विभिन्न सामुद्रिक जलडमरूमध्यों को लेकर चिंतित है, ''मलक्का जलडमरूमध्य'' अब सहयोग और सुरक्षा की एक संगठित संरचना का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है।

ऊर्जा सुरक्षा पर त्वरित प्रतिक्रिया

इन चारों देशों के बीच एक और महत्वपूर्ण समानता ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऊर्जा

सुरक्षा पर अलग समझौता किया है, जिसमें ईरान युद्ध जैसे संकटों के कारण ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, एलएनजी और विशेष रूप से भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के निर्यात को शामिल किया गया है। हालांकि यह प्रावधान 2015 के ''ऑस्ट्रेलिया–भारत परमाणु सहयोग समझौते'' का हिस्सा था, लेकिन अब तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। अब इसके कार्यान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

भारत और जापान ने भी ऊर्जा क्षेत्र में अलग समझौता किया है, जिसमें तेल और गैस उपभोक्ता देशों की आवाज को मजबूत करने तथा तीसरे देशों में ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की बात कही गई है।

इंडोनेशिया और भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन, एलएनजी और सौर ऊर्जा को अपनी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बनाया है। वहीं जापान इंडोनेशिया को सुरक्षित परमाणु ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोग कर सकता है।

पश्चिम एशिया में बढ़ती अस्थिरता के कारण ये सभी देश ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित हैं। हाल के वर्षों में कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। भारत ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रबंधन किया, जबकि जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं अधिक संवेदनशील स्थिति में पहुंच गई थीं।

साझा मूल्य और नई क्षेत्रीय सोच

इंडो–पैसिफिक की इस उभरती व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार साझा मूल्य प्रणाली भी है। यह केवल ''फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक'' की अवधारणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और यूक्रेन के संदर्भ में सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। यही भावना अन्य द्विपक्षीय समझौतों में भी दिखाई देती है।

यह केवल नैतिकता का प्रश्न नहीं है। इन देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान उनकी अपनी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यदि दुनिया के किसी हिस्से में नियमों की अनदेखी होती है, तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है।

अमेरिका और चीन के बीच संतुलन

यद्यपि चीन की गतिविधियां इन सभी देशों के लिए चिंता का विषय हैं, लेकिन यह पूरी रणनीति केवल बीजिंग को लेकर नहीं है।

यह अमेरिकी नीति की बढ़ती अनिश्चितता के प्रति भी प्रतिक्रिया है। विशेष रूप से ''शांग्री–ला संवाद'' में अमेरिकी रक्षा मंत्री ''पीट हेगसेथ (च्मजम भ्महेमजी)'' द्वारा सहयोगी देशों से रक्षा खर्च को अमेरिका के 3.5 प्रतिशत मानक के बराबर लाने की मांग ने कई देशों को असहज किया।

उन्होंने अधिक रक्षा खर्च करने वाले देशों को तेज हथियार आपूर्ति और विशेष सहयोग का आश्वासन दिया, जबकि अन्य देशों के लिए कड़े संकेत दिए। यह ऐसे समय में हुआ जब ये सभी देश ईरान और यूक्रेन युद्धों के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे हैं। साथ ही, अमेरिकी टैरिफ नीतियों ने भी इन देशों को प्रभावित किया है।

इंडोनेशिया को हाल ही में अमेरिका के साथ Agreement on Reciprocal Trade करना पड़ा, जिससे उस पर प्रस्तावित 32 प्रतिशत शुल्क घटकर 19 प्रतिशत रह गया।

दक्षिण तट रेलवे के महाप्रबंधक ने कार्यस्थल सुरक्षा एवं रेलमदद प्रदर्शन की समीक्षा की

(पेन पॉवर न्यूज):
विशाखापट्टनम, पेन पॉवर ,14 जुलाई: दक्षिण तट रेलवे के महाप्रबंधक श्री संदीप माथुर ने दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय में कार्यस्थल सुरक्षा, रेलमदद शिकायत निवारण प्रणाली तथा यात्री शिकायतों के प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान महाप्रबंधक ने कहा कि पूरे जोन में कार्यस्थल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने, कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा कार्यस्थलों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की असुरक्षित कार्यप्रणाली को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा संस्कृति विकसित करना अत्यंत आवश्यक है।
रेलमदद शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा करते हुए श्री माथुर ने अधिकारियों को लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक यात्री शिकायत का समयबद्ध, पेशेवर एवं संतोषजनक समाधान किया जाए तथा शिकायत के निस्तारण के बाद गुणवत्तापूर्ण फीडबैक भी प्रदान किया जाए।
महाप्रबंधक ने विभागों को शिकायतों की प्रवृत्तियों पर लगातार नजर रखने, बार–बार सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करने तथा सेवा गुणवत्ता एवं यात्री संतुष्टि में सुधार के लिए आवश्यक निवारक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में दक्षिण तट रेलवे के प्रमुख विभागाध्यक्ष तथा चारों मंडलों कृविशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकलकृके मंडल रेल प्रबंधकों ने भाग लिया। बैठक में अपने–अपने मंडलों में चल रही सुरक्षा पहलों एवं शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा की गई।

जगन ने रायलसीमा को बर्बाद कर दिया: सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी

(पेन पॉवर न्यूज):
नेल्लोर जिला, 14 जुलाई: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और सर्वेपल्ली विधायक सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन ने रायलसीमा के हितों को भारी नुकसान पहुंचाया है।
मंगलवार को नेल्लोर में मीडिया से बातचीत करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी नेताओं को "ताडेपल्ली पैलेस" में आत्ममंथन बैठक आयोजित कर यह समीक्षा करनी चाहिए कि उन्होंने रायलसीमा के लिए वास्तव में क्या किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी राजनीतिक रूप से बेरोजगार नेताओं के लिए निरर्थक बैठकें आयोजित कर रही है।

"गन कल्चर के जरिए क्षेत्रीय विवाद पैदा करना बंद करें"

सोमिरेड्डी ने जगन और उनके सहयोगियों को सलाह दी कि वे रायलसीमा, उत्तर आंध्र और तटीय आंध्र के बीच "गन कल्चर" की राजनीति के माध्यम से विवाद पैदा करने की कोशिशें बंद करें।
उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी नेताओं को रायलसीमा और नेल्लोर के विकास एवं सिंचाई परियोजनाओं पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, जगन के पांच साल के शासनकाल में इन परियोजनाओं पर केवल 2,000 करोड़ खर्च किए गए।
इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि गठबंधन सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में रायलसीमा और नेल्लोर जिले की परियोजनाओं पर 12,000 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं और अतिरिक्त 10,000 करोड़ भी आवंटित किए हैं।
सोमिरेड्डी ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार ने बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए और आवंटित धन का 40 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया। उन्होंने कृषि, सड़क एवं भवन तथा जल संसाधन विभागों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया।
"क्या रायलसीमा लिफ्ट योजना जगन के शासनकाल में नहीं रुकी थी?"
सोमिरेड्डी ने सवाल किया कि रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जगन के कार्यकाल में ही नहीं रोका था क्या?
उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व तेलंगाना मंत्री और बीआरएस नेता टी. हरीश राव ने स्वयं दावा किया था कि उनकी पार्टी ने इस परियोजना को रुकवाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन ने जलयज्ञम जैसी महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना को "धनयज्ञ" में बदल दिया और इस मुद्दे पर अदालतों की आलोचना भी झेलनी पड़ी।
सोमिरेड्डी ने पूछा कि जो लोग रायलसीमा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) योजना को बंद कर

चुके हैं, वे अब क्षेत्र के हितों की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन ने किसानों के प्रति बेहद उदासीन और अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया।
अपने वक्तव्य के अंत में सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी नेताओं को रायलसीमा की परियोजनाओं और विकास पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी और कहा कि वे इस पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं।

ई–केवाईसी नहीं तो गैस सिलेंडर बुकिंग बंद

(पेन पॉवर न्यूज):
सुल्लूरुपेटा (तिरुपति जिला): जिन एलपीजी उपभोक्ताओं ने 30 जून तक अपना ई–केवाईसी (म–ज्ञल्ब) पूरा नहीं कराया है, उनकी गैस सिलेंडर बुकिंग सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
तेल कंपनियों ने कई बार चेतावनी दी थी कि ई–केवाईसी न कराने पर भविष्य में परेशानी हो सकती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अनेक उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप तिरुपति जिले में हजारों उपभोक्ता गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं।
ई–केवाईसी पूरा करने के बाद ही उनकी बुकिंग दोबारा शुरू की जाएगी।
अवैध कनेक्शनों पर रोक
पूर्व में दीपम योजना के तहत लाभार्थियों को बिना सुरक्षा जमा राशि के मुफ्त गैस कनेक्शन, चूल्हा और रेगुलेटर दिए गए थे। इसके अलावा कई उपभोक्ता प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (च्डन्ल्) के तहत सब्सिडी भी प्राप्त कर रहे हैं।
अनुमान है कि जिले में लगभग 2 लाख लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
पहले ई–केवाईसी अनिवार्य नहीं होने के कारण, कई मामलों में उपभोक्ता की मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर गैस कनेक्शन अनौपचारिक रूप से उपयोग

किए जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे कनेक्शनों से सिलेंडर बुक कर उन्हें काले बाजार में बेच रहे थे।
अब चूंकि ई–केवाईसी उसी व्यक्ति को कराना होगा जिसके नाम पर कनेक्शन पंजीकृत है, इसलिए ऐसे अनधिकृत कनेक्शनों पर स्थायी रूप से रोक लगने की संभावना है।
अनुमान के अनुसार:
लगभग 10: उपभोक्ताओं ने ई–केवाईसी नहीं कराया है।
इनमें से 5: मृत उपभोक्ताओं के नाम पर चल रहे कनेक्शन हैं।
करीब 3: सक्रिय उपभोक्ता हैं जिन्होंने अभी तक ई–केवाईसी नहीं कराया।
लगभग 2: वृद्ध उपभोक्ता हैं जिनकी उंगलियों के निशान सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं।
ई–केवाईसी न होने पर गैस सिलेंडर बुकिंग बंद रहेगी और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली गैस सब्सिडी भी खाते में जमा नहीं होगी।
ऐसे करें कनेक्शन पुनः चालू
जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग बंद हो गई है, वे अपना गैस कनेक्शन दोबारा सक्रिय कर सकते हैं।
अपने आधार कार्ड के साथ गैस एजेंसी जाएं।
एजेंसी कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक जानकारी लेकर मुफ्त में ई–केवाईसी पूरा करेंगे।
गैस डिलीवरी कर्मियों के पास भी ई–केवाईसी मशीनें उपलब्ध रहती हैं, उनके माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
ई–केवाईसी पूरा होते ही गैस कनेक्शन तुरंत पुनः सक्रिय कर दिया जाएगा।
बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा
जिन बुजुर्गों की उंगलियों के निशान सत्यापित नहीं हो रहे हैं, वे आधार सेवा केंद्र जाकर अपनी आईरिस (आंखों की पुतली) बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करा सकते हैं। इसके माध्यम से ई–केवाईसी पूरा किया जा सकता है।
इसके अलावा, यदि कनेक्शन किसी अशक्त या चलने–फिरने में असमर्थ बुजुर्ग के नाम पर है, तो उसे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर स्थानांतरित भी कराया जा सकता है।

'जिहादी ऐसे सेलिब्रिटीज का हवाला देते हैं'

बीजेपी मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी पर दिए अपने 'लव जिहाद' वाले बयान का बचाव किया

ठाणे: कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर तंज कसते हुए सवाल उठाया था कि क्या आमिर खान 'लव जिहाद' के ब्रांड एंबेसडर बन रहे हैं। बुधवार को राणे मुंबई स्थित द फ्री प्रेस जर्नल के कार्यालय पहुंचे। वहां जब उनसे आमिर खान को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान का बचाव किया।
उन्होंने कहा, ''मैंने विशेष रूप से कहा था कि वह लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हो सकते हैं। एक हिंदू कार्यकर्ता के रूप में जब हम कई पीड़ितों से मिलते हैं, उनके माता–पिता से बात करते हैं, तब हमारी बहनें, जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं, बताती हैं कि संबंधित जिहादी उनसे नजदीकी बढ़ाने के लिए ऐसे सेलिब्रिटीज का हवाला देते हैं। वे खुद की तुलना भी इन सेलिब्रिटीज से करते हैं।'' राणे

ने आगे कहा, ''वे उनसे कहते हैं, 'उन्हें देखो, वे कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। तुम भी वही रास्ता क्यों नहीं अपनाती?' इसलिए जब मैंने कहा कि वह लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर हो सकते हैं, तो उसका कारण यह है कि हमने ऐसे पीड़ितों से मुलाकात की है जो इन सेलिब्रिटीज की जीवनशैली से प्रभावित होकर जाल में फंस गए।'' राणे ने आगे कहा कि जब कोई व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसके लाखों अनुयायी होते हैं, तो उसे अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। मंत्री ने कहा, ''एक हिंदू के रूप में मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वे इसका दूसरा पक्ष भी जानें और इस बात को लेकर सतर्क रहें कि वे किससे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि पर्दे पर और वास्तविक जीवन में बहुत अंतर होता है। पर्दे पर वह एक किरदार निभाते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वह वही व्यक्ति होते हैं जो वह वास्तव में हैं। इसी संदर्भ में मैंने वह बयान दिया था।

बिदादी टाउनशिप विवाद:

सर्वे के दौरान किसानों पर अधिकारियों से मारपीट का आरोप, देवेगौड़ा ने आंदोलन की चेतावनी दी

बेंगलुरु: बेंगलुरु के बाहरी इलाके में प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना पिछले चार महीनों से विवादों में घिरी हुई है। अब यह विवाद और गर्मा गया है, क्योंकि परियोजना का विरोध कर रहे किसानों पर भूमि सर्वेक्षण के लिए पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार इस परियोजना को तुरंत वापस नहीं लेती है, तो वह किसानों के साथ धरने पर बैठेंगे।
यह घटना सोमवार शाम की है, जब राजस्व विभाग के अधिकारी परियोजना क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि किसानों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, ने झाड़ुओं और अन्य वस्तुओं से महिला अधिकारियों पर हमला किया, जबकि पुरुष किसानों ने पुरुष अधिकारियों से मारपीट की। पुलिस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो कुछ पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया, जिससे चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।
मंगलवार सुबह बिदादी पुलिस ने अधिकारियों पर हमले के आरोप में 11 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे आंदोलनरत किसानों में और

अधिक आक्रोश फैल गया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने कहा, ''इस उम्र में मुझे सड़कों पर उतरकर धरने पर बैठने के लिए मजबूर मत कीजिए। यदि सरकार किसानों पर अत्याचार जारी रखती है, तो मैं स्वयं आंदोलन में शामिल होकर ध रना दूंगा।'' 93 वर्षीय नेता ने यह बात मीडिया से बातचीत के दौरान कही।

बिदादी परियोजना पर राजनीतिक संघर्ष

बिदादी टाउनशिप परियोजना को लेकर कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के बीच लंबे समय से राजनीतिक टकराव चल रहा है। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही थी, जबकि केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह किसानों के हितों के खिलाफ है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि डी. के. शिवकुमार बिदादी टाउनशिप के विकास के नाम पर रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं।
बिदादी क्षेत्र राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वोक्कालिगा बहुल रामनगर जिले में आता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि डी. के. शिवकुमार इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर लेते हैं, तो वोक्कालिगा समुदाय में उनका प्रभाव और मजबूत हो सकता है।
इस बीच, भाजपा एमएलसी सी. टी. रवि ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि तानाशाही की तरह व्यवहार कर रही है। बिदादी टाउनशिप का किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।''
कुमारस्वामी के विरोध के बाद परियोजना क्षेत्र के किसानों में भी मतभेद उभर आए। जेडी(एस) प्रभाव वाले क्षेत्रों के किसान अपनी जमीन देने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य किसान सरकार के पक्ष में हैं।
सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री रहते इस क्षेत्र को 'रेड जोन' घोषित किया गया था, जहां खेती के अलावा अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद परियोजना क्षेत्र के कम से कम आठ गांवों के किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के बदले प्रति एकड़ 2.5 करोड़ रुपये तक मुआवजा और विकसित टाउनशिप क्षेत्र में एक प्लॉट देने की भी घोषणा की है। इसके बावजूद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और बिदादी टाउनशिप का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में प्रमुख विषय बन गया है।

कृषि अधिकारी श्रीहरि हत्या मामले में नया मोड़, मुख्य आरोपी हरिकृष्ण ने परिवार सहित की आत्महत्या

प्रकाशम जिला: कृषि अधिकारी (एओ) श्रीहरि की हत्या के मामले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी हरिकृष्ण ने अपने परिवार के साथ सिंगरायकोंडा के पास ट्रेन के सामने आकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, इस घटना में हरिकृष्ण, उनकी पत्नी और उनके दो छोटे बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि संपत्ति विवाद के चलते हरिकृष्ण ने अपने साले और कृषि अधिकारी श्रीहरि की कथित रूप से हत्या की थी। पुलिस का मानना है कि हत्या मामले की जांच तेज होने के कारण हरिकृष्ण मानसिक तनाव में था और उसने परिवार सहित यह कदम उठाया। इस बीच, मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में नेल्लोर जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजिता वेजेंडला ने बुच्चिरेड्डीपालेम सर्किल इंस्पेक्टर (सीआई) और सब–इंस्पेक्टर (एसआई) को निलंबित कर दिया है। साथ ही, बुच्चिरेड्डीपालेम पुलिस स्टेशन के 23 पुलिसकर्मियों का तबादला भी किया गया है।

राजनीति के लिए ही विशाखापट्टनम आए हैं वाई.एस. जगन: पल्ला श्रीनिवास राव

(पेन पॉवर न्यूज):
विशाखापट्टनम, 14 जुलाई: तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने वाईएसआरसीपी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के विशाखापट्टनम दौरे पर प्रतिक्रिया दी। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पल्ला ने जगन को सलाह दी कि वे अब भी "शव राजनीति" करना बंद करें। उन्होंने मांग की कि जगन पहले यह स्पष्ट करें कि वे विशाखापट्टनम किस उद्देश्य से आए हैं। पल्ला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रहते हुए जगन ने एक भी मछुआरे को न्याय नहीं दिलाया। उन्होंने कहा कि मछुआरों को कानून के अनुसार मिलने वाली बकाया राशि भी उनकी सरकार ने नहीं चुकाई। उन्होंने सवाल किया कि आखिर जगन ने मछुआरों के लिए क्या किया है। पल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान मछुआरों के लिए निर्धारित निधियों को दूसरी जगहों पर मोड़ दिया गया था। उन्होंने यह भी पूछा कि पूर्व मंत्री सीदिरी अप्पलराजू के बेटे से जुड़े हालिया दुर्घटना मामले पर जगन चुप क्यों हैं। पल्ला ने कहा कि गठबंधन सरकार हमेशा मछुआरों के साथ खड़ी रहेगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। अंत में उन्होंने आरोप लगाया कि जगन का विशाखापट्टनम दौरा केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के उद्देश्य से किया गया है।

राम मंदिर चोरी का बचाव कर ट्रोल हुए अनुपम खेर

कहा– मुगलों ने मंदिरों में रेप किए उनकी लूट के सामने ये मामूली चीज

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुई चोरी के बचाव में दिए अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अनुपम खेर ने राम मंदिर में 2 से 7 करोड़ रुपए की अनियमितता को मामूली बात बताया। उन्होंने इसका कनेक्शन सीधे मुगलों से जोड़ते हुए कहा कि मुगलों ने जो देश को लूटा और अत्याचार किए, उसके सामने यह चोरी बहुत छोटी चीज है। इस बयान का वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर वायरल होने के बाद लोग उनकी जमकर आलोचना कर हैं।

इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने मंदिर में हुई चोरी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोग इसे बहुत बड़ी बात बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मंदिर में लूट मची है। एक्टर ने तर्क दिया कि लूट तब मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि लूट तब मची थी जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मारकर उनके जनेऊ को इकट्ठा करके तोला था। अनुपम खेर के मुताबिक, इतिहास में महिलाओं के साथ मंदिर रेप हुए, वे बहुत बड़ी समस्याएं थीं। अगर देश उन बड़ी दिक्कतों से उबर सकता है, तो यह चोरी बहुत छोटी चीज है।

अनुपम खेर का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल होते ही लोगों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। एक यूजर ने लिखा अनुपम जी 1000 साल पुराने इतिहास की बातें करके क्या वे इस तरह की गलत चीजों का समर्थन कर रहे हैं? अगर कोई आपका घर लूट ले और आपको (राम मंदिर मामले की तरह) भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाए, तो क्या यह कहना सही होगा कि इसे किसी का लालच मानकर छोड़ दिया जाए।

वहीं, एक अन्य यूजर ने सत्ताधारी पार्टी के गलत कामों और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बहस में मुगलों का नाम घसीटना बंद करने की सलाह दी।

उसनें लिखा कि सरकार का बचाव करने की इतनी क्या मजबूरी है, जबकि मंत्रियों और उनके सहयोगियों का लालच सड़कों और ईंधन से लेकर मंदिर के दान तक हर जगह साफ दिखाई दे रहा है।

सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं पवन कल्याण मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू

एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की मुंबई के एक अस्पताल में दाएं कंधे की सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद अब उनकी हालत धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। सर्जरी के अगले ही दिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। जनसेना पार्टी ने इस मुलाकात की एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है।

पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अस्पताल पहुंचे, पवन कल्याण से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। फोटो में पवन कल्याण कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके दाएं कंधे पर पट्टी बंधी हुई है।

पत्नी अन्ना लेझनेवा ने भी दिया अपडेट

पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा ने भी सर्जरी के बाद उनकी हेल्थ को लेकर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पवन हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दर्द से ऊपर रखते हैं और बहुत कम शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा, 'फिलहाल मेरा काम सिर्फ उनका ख्याल रखना है और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो सुरक्षित हाथों में हैं। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।'

क्यों करवानी पड़ी सर्जरी?

पवन कल्याण को 2016 में कंधे में चोट लगी थी। इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी लेकिन इसके बावजूद वह कई इवेंट्स में शामिल होते रहे। साथ ही अपनी राजनीति यात्राओं और चुनाव प्रचार के दौरान वह पार्टी कार्यकर्ता, फैंस से मिलते थे। जहां पर लोग उनका हाथ पकड़ते थे। इस दौरान उनके हाथ पर जोर पड़ता और उनको दर्द होता है। बाद में यह दर्द बढ़ता ही गया। आखिर में डॉक्टर्स ने सर्जरी करने को कहा। लेकिन दोनों कंधों की सर्जरी एक साथ न करने की सलाह दी। ऐसे में आज उनकी दाहिने कंधे की सर्जरी हुई। यह सर्जरी तीन घंटे तक चली।

पवन कल्याण के बाएं कंधे की सर्जरी दो महीने बाद की जाएगी। बता दें कि उनके कंधे के रोटेटर कफ में चोट लगी थी।

जुरासिक पार्क एक्टर सैम नील का निधन

78 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, ब्लड कैंसर को दे चुके थे मात

हॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'जुरासिक पार्क' और ऑस्कर विजेता फिल्म 'द पियानो' एक्टर सैम नील का सोमवार को 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस दुखद खबर की पुष्टि की।

परिवार के बयान के अनुसार, सैम नील का निधन अचानक हुआ। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सैम कैंसर से पूरी तरह ठीक हो चुके थे। साल 2023 में उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें एंजियोइम्यूनोब्लास्टिक टी-सेल लिम्फोमा नाम का एक दुर्लभ ब्लड कैंसर हुआ था। इलाज के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। फिलहाल परिवार ने उनके निधन की वजह नहीं बताई है।

सैम नील को उनकी दमदार और सहज एक्टिंग के लिए जाना जाता था। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता 'जुरासिक पार्क' में डॉ. एलन ग्रांट के किरदार से मिली।

सैम नील न्यूजीलैंड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक थे। उनका पूरा नाम नाइजल जॉन डर्मॉट सैम नील था। उनका जन्म 14 सितंबर 1947 को उत्तरी आयरलैंड के ओमाघ में हुआ था। जब वे छोटे थे, तब उनका परिवार न्यूजीलैंड जाकर बसा, जहां उनकी परवरिश हुई।

सैम नील ने 1970 के दशक में अभिनय की शुरुआत की। उन्हें पहली बड़ी पहचान 1977 की फिल्म स्लीपिंग डॉग्स से मिली। इसके बाद 1979 की माय ब्रिलियंट करियर ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने हॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई। सैम नील उन कलाकारों में शामिल थे, जिन्होंने 1970 के दशक के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई। उनका फिल्मी करियर पांच दशक से ज्यादा लंबा रहा और उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता।

महेश मांजरेकर की पत्नी को कैंसर

मेधा मांजरेकर ने शेयर किया पोस्ट, बीमारी ने सब बदल दिया

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और फिल्ममेकर महेश मांजरेकर की पत्नी मेधा मांजरेकर ने कैंसर से जंग को लेकर खुलासा किया है। मराठी एक्ट्रेस मेधा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बीमारी के बारे में इंस्टाग्राम पर एक लंबा और भावुक नोट शेयर किया। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें और अस्पताल की झलकियां भी शेयर की हैं।

मेधा मांजरेकर 58 साल की हैं। वह मराठी सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। साल 1995 में मेधा ने महेश मांजरेकर से शादी की थी, जिसके बाद 2001 में उन्होंने बेटी सई मांजरेकर को जन्म दिया। यह महेश मांजरेकर की दूसरी शादी है। माता-पिता की तरह सई भी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने 2019 में सलमान खान के अपोजिट 'दबंग 3' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में मेधा मांजरेकर भी जानकी के रोल में थीं।

मेधा मांजरेकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कैंसर से लड़ाई की अपनी लंबी यात्रा पर बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उन्होंने अपना ध्यान बीमारी से हटाकर उन लोगों पर लगाया, जिन्होंने उनका साथ दिया। मेधा ने पति महेश मांजरेकर के सपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा है, 'जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा के लिए बदल देते हैं। यह भी उनमें से एक था। जब मेरे इलाज का एक दौर खत्म हो रहा है और मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो मैं पीछे मुड़कर देख रही हूं।

बीमारी का पता चलने पर नहीं, सर्जरी पर नहीं, कीमोथेरेपी पर नहीं, रेडिएशन पर नहीं। मुझे बस ईश्वर की कृपा याद आती है।'

ओटीटी पर रिलीज होगी 'तीसरी बेगम'

फिल्म निर्माता और निर्देशक के. सी. बोकाडिया की चर्चित फिल्म 'तीसरी बेगम' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। सिनेमाघरों में प्रदर्शन के बाद यह फिल्म 18 जुलाई 2026 से 'वेव्स' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी।

यह फिल्म एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया है।

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में जरीना वहाब, मुग्धा गोडसे और कायनात अरोड़ा नजर आएंगी। बोकाडिया ने उम्मीद जताई है कि सिनेमाघरों की तरह ओटीटी पर भी इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा।

निर्देशक के. सी. बोकाडिया ने फिल्म की कहानी को लेकर खुलासा किया कि यह फिल्म पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने बड़े गर्व के साथ अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी से उनका परिचय कराया। ये तीनों पत्नियां अलग-अलग समुदायों से ताल्लुक रखती थीं।

बोकाडिया के मुताबिक, उस समय तीसरी पत्नी के चेहरे पर जो झिझक और दर्द दिखाई दिया, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इसी घटना के बाद उन्होंने इस संवेदनशील विषय पर फिल्म बनाने का फैसला किया।

के. सी. बोकाडिया का कहना है कि 'तीसरी बेगम' सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक आईना है। यह कहानी दर्शकों को समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सिनेमाघरों में सराहनीय प्रदर्शन करने के बाद अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोग इस फिल्म को पसंद करेंगे। यह फिल्म मुख्य रूप से महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई को दिखाती है।

के. सी. बोकाडिया भारतीय सिनेमा के एक बड़े और प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है।

उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, शाह रुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार, सनी देओल, अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े कलाकारों की फिल्मों का निर्देशन किया है।

उन्होंने 'तेरी मेहरबानियां', 'प्यार झुकता नहीं', 'नसीब अपना अपना', 'आज का अर्जुन' और 'फूल बने अंगारे' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं।

सोहेल खान ने सीमा से तलाक पर किया खुलासा

कहा– काम ठीक नहीं चल रहा था, अपने बर्ताव के कारण मैंने उसे खो दिया

बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं। शो के हालिया एपिसोड में दो वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई, जिनमें से एक सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सजदेह हैं। शो के सेट पर दोनों का रीयूनियन काफी सकारात्मक रहा और दोनों एक-दूसरे से मिलकर खुश नजर आए। इस दौरान सोहेल खान ने सीमा से अपने तलाक की वजहों पर खुलकर बात की। उन्होंने शादी टूटने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उस समय उनका काम ठीक नहीं चल रहा था और अपने खराब बर्ताव की वजह से उन्होंने सीमा को खो दिया।

शो के दौरान जब सीमा सजदेह की एंट्री हुई, तो सोहेल ने उनके लिए ग्रीन टी बनाई। इस पर शो के होस्ट निखिल चिनापा ने सोहेल से पूछा कि औरत घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है, आपके घर में किसका हाथ था? इसका जवाब देते हुए सोहेल खान ने कहा कि उस समय मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी।

सोहेल खान ने शो में कंटेस्टेंट जैद दरबार से बातचीत के दौरान अपने बच्चों और सीमा के रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे निर्वाण और योहान फिलहाल सोहेल के साथ ही रहते हैं। वहीं, सीमा बच्चों से मिलने के लिए हफ्ते में तीन बार उनके घर आती हैं। सोहेल ने खुलासा किया कि सीमा के पास आज भी उनके घर की चाबी है। सीमा ने शो में बताया कि उनका छोटा बेटा योहान शो में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जबकि बड़ा बेटा निर्वाण चाहता है कि सोहेल खान यह शो जीतें।

सोहेल और सीमा की पहली मुलाकात चंकी पांडे की सगाई की पार्टी में हुई थी। सोहेल पहली नजर में ही सीमा को दिल दे बैठे। जल्द ही दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अलग-अलग धर्म होने की वजह से सीमा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया।

15 मार्च 1998 को, जिस दिन सोहेल की पहली डायरेक्टेड फिल्म 'प्यार किया तो डरना क्या' रिलीज हुई, उसी दिन दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। पहले आर्य समाज मंदिर में फेरे लिए और फिर निकाह किया। उनका पहला बेटा निर्वाण 2000 में और दूसरा बेटा योहान 2011 में हुआ। दोनों 2022 में अलग हो गए।

दलजीत कौर ने प्यार को कहा 'तुच्छ चीज'

दो शादियां टूटने पर उठी टीस– 20 साल बाद शायद मोहब्बत हो, अभी नहीं

एक्ट्रेस दलजीत कौर ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ कहा। जीवन में बहुत कुछ झेलने वाली एक्ट्रेस ने अपने कमजोर पलों, शांति पाने, अपने जीवन को फिर से सही करने और ताकत के साथ नया चैप्टर शुरू करने के बारे में बात की। खुलकर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि क्या उन्हें अब भी प्यार पर भरोसा है या नहीं।

खुलकर बोलते हुए दलजीत कौर ने कहा, 'मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती। प्यार को कम आंका गया है। कभी मत कहना.. चलो। 15-20 साल बाद हो सकता है, मैं 60-70 की हो जाऊं शायद। इस वक्त प्यार मैंने इतने फालतू तरीकों से देखा, क्या मतलब है आप 45-46 के हो और किसी औरत को अपने प्यार में पागल कर देते हो। फिर मतलब आप धूम-धाम से लेके गए और वहां आप दूसरी लड़की के चक्कर में हो।'

एक्ट्रेस ने युवा पीढ़ी की तारीफ करते हुए कहा, 'युवा पीढ़ी अधिक समझदार है। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है वो दुर्भाग्यवश गलत परवरिश की गई है। उन्हें हमेशा ये बोला गया कि अरे आप तो मर्द हो, आप तो शेर हो। इस बकवास में बड़ा करके कि उन्हें असली में लगने लगा कि वो शेर हैं।' बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट ने प्यार को एक 'तुच्छ' चीज बताया और इस बात पर जोर दिया कि सम्मान कितना जरूरी है।

राम कपूर को सुनकर रो पड़ीं जेनेलिया

हाल ही में 'लॉक अप 2' में राम कपूर ने अपनी टीनएज के एक दर्दनाक वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ 13 साल के थे और बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात सबसे छिपाकर रखी थी और सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर को ही इसके बारे में पता था। एपिसोड आने के तुरंत बाद, राम की पत्नी गौतमी उनके सपोर्ट में सामने आईं और ईमानदारी और हिम्मत के साथ सच बताने के लिए उनकी तारीफ की।

शो के होस्ट रितेश देशमुख ने भी उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी को री-शेयर किया और अपनी जिंदगी के इतने निजी और मुश्किल हिस्से के बारे में खुलकर बात करने के लिए राम की तारीफ की। अब जिनिलिया देशमुख ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि राम की इस बात ने उन्हें भावुक कर दिया।

सोशल मीडिया पर दिल को छू लेने वाला नोट शेयर करते हुए, जिनिलिया ने राम कपूर की हिम्मत की तारीफ की और 'लॉक अप 2' में हुई ईमानदार बातचीत के लिए शो की सराहना की।

उन्होंने लिखा, 'राम कपूर आपने मुझे रुला दिया और जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसे देखने का एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया दिखाया। #Lock-Upp2 एक अलग तरह का रियलिटी शो होने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है।'

दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप के बयान पर मुजम्मिल की सफाई

वीडियो में कहा था– मैंने उसे छोड़ा, पछतावा नहीं, मैं स्टार था

एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम अपने उस पुराने बयान से सुर्खियों में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि 2 साल तक दीपिका पादुकोण के साथ रहने के बाद उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने ये भी दावा किया था कि दीपिका ने खुद उन्हें प्रपोज किया था। अब वीडियो वायरल होने के बाद एक्टर ने सफाई दी है।

मुजम्मिल इब्राहिम ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'जिस इंटरव्यू की चर्चा की जा रही है और जिसे गलत तरीके से ताजा दावा बताकर पेश किया जा रहा है, वह वास्तव में एक साल से भी पहले रिकॉर्ड किया गया था।

इस समय जो क्लिप्स वायरल हो रही हैं, वे एक लंबी बातचीत के केवल कुछ छोटे हिस्से हैं।' ऐसे में जब बातचीत के कुछ अंशों को अलग करके देखा जाता है, तो उनका वास्तविक अर्थ और संदर्भ बदल सकता है।' कुछ महीनों पहले एक पॉडकास्ट में सिद्धार्थ कानन ने मुजम्मिल से पूछा था कि क्या आप दीपिका पादुकोण के साथ रिलेशनशिप में थे। मुजम्मिल ने इस बारे में बात करने से इनकार करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे और अब भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं।'

जश्न में डूबा महेश बाबू का परिवार

साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में बिजी हैं। इस बीच उनका परिवार खुशी के माहौल में है। इटली में उनके भतीजे और युवा एक्टर सिद्धार्थ घट्टामनेनी की शादी का जश्न शुरू हो गया है। महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने हाल ही में इस खुशी के मौके पर परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों की तस्वीरें शेयर कीं।

नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की शादी के जश्न की कई तस्वीरें शेयर कीं हैं। वह गहरे गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने स्टाइलिश ज्वेलरी के साथ अपना लुक पूरा किया है।

तस्वीरों में वह परिवार के सदस्यों के साथ खुशी के पल बिताती हुई नजर आईं।

Printed and Published by **GANTYADA APPARAO** on behalf of **GANTYADA APPARAO**, Printed at Sri Sai Ganga Printers and Publishers Flat No: 504, Bharat Towers, 5th Lane, Dwaraka Nagar, Visakhaptanam, Andhra Pradesh-530016, and Published at H.NO: 38-4-216, MAHARANI STREET, MARRIPALEM, Visakhapatnam, Andhra Pradesh-530018, **Editor: GANTYADA APPARAO.** Mobile : 9059465965, **RNI : APHIN/26/A3657**, editorpenpower@gmail.com